हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 25 फ़रवरी 2026, समय 1305 (5 मिनट)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का 31 मार्च तक शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति स्कीम की प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय निधियों का समय पर कुशल उपयोग जरूरी है।

****

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदर्शन करने या सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष द्वारा सदन के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करना उचित नहीं। उन्हें सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री कल हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए प्रदर्शन पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी को अपनी बात कहने के लिए स्थान की आवश्यकता है, तो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में प्रदर्शन हेतु स्थान आरक्षित किया गया है। वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण सभी सदस्यों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो इस सदन की परंपरा है।उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे सदन के संरक्षक हैं और सरकार इस संबंध में उनके हर निर्णय के साथ खड़ी है।

****

हरियाणा में पेंशन के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो 31 जनवरी तक 2,75,441 हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने विधानसभा के बजट सत्र में एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को यह जानकारी दी।

पेंशन रोके जाने को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि मृत्यु, आयु के कारण अयोग्यता, आय अयोग्यता, राज्य से बाहर चले जाने तथा पुनर्विवाह इत्यादि जैसी विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के दस्तावेजों को सत्यापित करने के कारण 1 लाख 11 हजार 120 लोगों की पेंशन रोकी गई।

****

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबद्ध सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी की शैक्षिक व मुक्त विद्यालय एवं डी०एल०एड० की द्वितीय वर्ष की रि-अपीयर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं।

बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी की शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में प्रदेशभर में करीब 1431 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।अधिकतर परीक्षा केन्द्र सीसीटीवी कैमरो की निगरानी में रखे गए हैं।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण हेतु 320 उड़नदस्तों का गठन किया गया है तथा परीक्षा केंद्रों के निकट फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रश्न पत्रों पर अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्यू आर कोड और हिडन सिक्योरिटी फीचर भी अंकित किए गए हैं। इससे यदि कोई परीक्षार्थी, पर्यवेक्षक, कर्मचारी व अन्य कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र की फोटो लेता है तो तुरंत पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र किस परीक्षार्थी का है एवं कहां से आउट हुआ है, जिससे परीक्षाओं के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि यदि किसी परीक्षा केन्द्र से पेपर आउट होने का मामला पाया जाता है, तो उस केन्द्र के अधीक्षक, पर्यवेक्षक व नकल में संलिप्त परीक्षार्थी के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

****

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि असंध विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुनक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा।वे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 24 जून 2019 को मुनक स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की घोषणा की थी और इसे 20 दिसंबर 2019 को अपग्रेड किया गया। इसके बाद, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को 2 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई और भवन के निर्माण के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा 25 जनवरी 2021 को 3 करोड़ 9 लाख रुपये का कार्य एजेंसी को आवंटित भी कर दिया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिक भुगतान किए जाने पर जांच की तो एजेंसी ने 20 प्रतिशत कार्य करने के

बाद वर्ष 2022 में काम रोक दिया और उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। एजेंसी द्वारा इस भवन की केवल चारदीवारी का निर्माण किया गया है। इस पर कुल 67 लाख 12 हजार रुपये खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी का अनुबंध 20 जून 2024 को समाप्त कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग को भवन निर्माण के लिए अनुमानित बजट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आरती सिंह राव ने बताया कि आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त होने के उपरांत पीएचसी भवन के निर्माण का कार्य लगभग 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

****